साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार 28 अगस्त-03 सितंबर 2023, वर्ष-9, अंक-20
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

-आईसीएआर ने दी विवि के विज्ञानिकों को जिम्मेदारी

-पशुओं की खासियत, आहार-आवास का करेंगे शोध

-गुण के आधार पर प्रजातियों की पहचान करनी होगी

-कई ऐसी प्रजातियां जिनको अब तक नहीं मिली पहचान

राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाम करेगा एमपी की मदद

मध्यप्रदेश के पशुओं को देश में मिलेगी पहचान

-प्रजातियों की पहचान करेगा वेटरनरी विश्वविद्यालय

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में अब मध्यप्रदेश की पशुओं को पहचान मिलेगी। इसके लिए नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के विज्ञानिकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक महत्वपूर्ण शोध की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें उन्हें मध्यप्रदेश के ग्रामीण आंचलों में जाकर वहां मिलने वाले पशुओं के गुण-दोष के आधार पर उनकी प्रजातियों की पहचान करनी होगी। इतना ही नहीं, क्षेत्र के आधार पर इनके आहार, आवास, बीमारी और इलाज जैसे सभी पहलुओं पर अध्ययन कर इन्हें देशभर में पहचान दिलानी होगी। संभवत: इस तरह की पहल पहली बार हो रही है। मप्र में आज भी छोटे और बड़े पशुओं की कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनकी अब तक पहचानी नहीं गई हैं। आम प्रजातियों की तुलना में कहीं बेहतर गुण मौजूद हैं। इस काम को अब जबलपुर वेटरनरी विवि, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो

गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी की क्षेत्रीय प्रजातियों की पहचान जरूरी

पशुओं में लगातार हो रहे शोध के दौरान विज्ञानिकों को सबसे ज्यादा दिक्कत प्रजातियों की पहचान को लेकर होती है। देशी पशुओं में आज गिनती की प्रजातियां ही चिंहित हैं। ऐसे में इनकी पहचान किए बिना न तो पर पर शोध किया जा सकता है और न ही पशुपालकों को इसका फायदा पहुंचाया जा सकता है। खासतौर पर गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी की क्षेत्रीय प्रजातियों की पहचान करना जरूरी हो गया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र की जलवायु, आहार और आवास के आधार पर बांटी है। अब इनकी पहचान एक बड़ी चुनौती हो गई है। इस पर जबलपुर वेटरनरी विवि के एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग एक्सपर्ट काम करेंगे। वे पांच साल के दौरान इस शोध पर काम करेंगे।

प्रजातियां बिखरी

आईसीएआर के राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के सहयोग से विवि के वैज्ञानिकों को इन पशुओं की जनसंख्या की जानकारी दर्ज करने के अलावा उनके प्रजनन विधि, शारीरिक माप, उत्पादन क्षमता को विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक क्षेत्रीय पशुओं की प्रजातियां पूरी तरह से बिखरी हुई हैं। इनका कोई डाटा भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी मदद से इन पर शोध किया जाए सकें।

यह होगा फायदा

प्रजातियों की पहचान के बार उनकी खासियत के आधार पर शोध होगा। उनकी संख्या बढ़ाने और उससे होने वाले फायदों से पशुपालकों को जोड़ा जाएगा। क्षेत्रीय प्रजातियां होने की वजह से आहार और आवास आसानी में उपलब्ध होगा। क्षेत्रीय पशुपालकों को भी इस शोध से सीधी तौर पर जोड़ा जाएगा। इन्हें होने वाली बीमारियों और प्रतिरोधक क्षमता पर विस्तार से काम होगा।

पशुओं से जुड़े अनुसंधानों को आगे बढ़ाने और उसके बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए प्रदेश में पशुओं की प्रजातियों की क्षेत्रीय स्तर पर पहचान जरूरी है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाम की मदद से हम शोध करने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश के लिए सबसे अहम है।
प्रो.एसपी तिवारी, कुलपति, जनेकृविवि

मध्यप्रदेश में गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी समेत अन्य स्वदेशी पालतु पशुओं की प्रजातियों का सर्वे किया जाएगा। इनमें मुख्य तौर पर क्षेत्रीय प्रजातियों का भौगिक सर्वे होगा, जिसमें उनके रहने, खाने सहित अन्य सभी पहलुओं का अध्ययन कर उनकी प्रजातियों की पहचान होगी।
डॉ.मोहन सिंह ठाकुर, मुख्य अन्वेशक, वेटरनरी विवि, जबलपुर

अधिकतम 10 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी

मध्यप्रदेश में लगेंगी 1772 सूक्ष्म खादय उद्यम इकाइयां, सबसे ज्यादा ग्वालियर-खरगोन में

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म खादय उद्यम की 1772 इकाइयां लगने जा रही हैं। इन इकाइयों के लिये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय उद्यम उन्नयन योजना में ऋण स्वीकृत हो चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 116 इकाइयां ग्वालियर में लगेंगी। दूसरे नम्बर पर 100 इकाइयां खरगोन में, रीवा में 47, बालाघाट में 23, टीकमगढ़ में 27 और होशंगाबाद में 22 इकाइयां लगेंगी। उल्लेखनीय है कि योजना में उदयमियों ने रुचि दिखाते हुए 10664 उदयमियों ने ऋण के लिए आवेदन किया था। परीक्षण के बाद 1772 को ऋण देने योग्य पाया गया। बाकी आवेदनों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा उदयमियों से आगे बढ़कर इस का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

बैतूल का उल्लेख

केन्द्र ने सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म खादय इकाइयों की सूची तैयार की है। इसमें मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के जमुना स्व-सहायता समूह की सफलता का उल्लेख है। इस समूह के सदस्यों को खादय प्रसंस्करण में प्रशिक्षण मिला। समूह ने आम का अचार बनाना शुरू किया। स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। इससे समूह को हर महीने 1000 रुपए की आय होने लगी। समूह के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता गया।

क्या है योजना में

खाद्य प्र-संस्करण उद्योग मंत्रालय ने मप्र की भागीदारी के साथ सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार में सहायता देने के लिए पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की है। इसमें कौशल प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जा रहा है। पूंजी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के लिए कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों को सहायता दी जा रही है।

15 जिलों में सामान्य से कम बारिश, किसानों की चिंता बढ़ी

भोपाल। जागत गांव हमार

अगस्त में दूसरी बार मानसून फिर शिथिल पड़ गया है। वर्तमान में प्रदेश को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली नहीं है। मानसून द्रोणिका का पश्चिमी सिरा हिमालय की तलहटी में पहुंच गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अब एक सप्ताह तक किसी मौसम प्रणाली के सक्रिय होने की संभावना नहीं दिख रही है। इस वजह से मौसम अब साफ होने के आसार हैं। मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस सीजन अभी तक प्रदेश में से नौ प्रतिशत कम वर्षा हुई है। 52 में से 15 जिलों में सामान्य से 40 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है। सिर्फ चार जिलों में ही सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। मानसून द्रोणिका का पूर्वी सिरा गोरखपुर से होकर जा रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने के कारण मानसून की गतिविधियों में कमी आने लगी है। मौसम अब धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। बादल छंटने के कारण धूप निकलेगी। इससे तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। हालांकि, तापमान बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं।

किसान एक साल में चार बार ले रहा उत्पादन

अशोकनगर में खीरे से किसान बना लखपति

कभी अधिक बारिश, तो कभी फसलों में बीमारी के कारण लागत भी मुश्किल से निकल पाती थी

अशोकनगर। जागत गांव हमारा

अशोकनगर जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर बलनाई गांव। यहां रहने वाला युवा किसान मोहन सिंह। खीरे और टमाटर की खेती ने मोहन सिंह की किस्मत बदल डाली। एक समय था जब, परिवार परंपरागत खेती करता आ रहा था। कभी अधिक बारिश, तो कभी फसलों में बीमारी के कारण लागत भी बमुश्किल निकल पाती थी। इसके बाद मोहन सिंह ने ऐसी फसलों पर फोकस किया, जो कम लागत और कम समय में अधिक मुनाफा दे सके। आठ साल पहले मोहन सिंह ने सब्जियों की खेती शुरू की। इसमें खीरा और टमाटर की खेती पर ज्यादा फोकस किया। पहली बार की पैदावार ने साबित कर दिया कि यही विकल्प बेहतर है। कारण- ये दोनों फसल ऐसी हैं जो कि सालभर आमदनी का जरिया बनी रहती है। सालभर में खीरे की चार फसल लेते हैं। एक सीजन में 2 से लेकर ढाई लाख तक की आमदनी सिर्फ खीरे से हो रही है, जबकि एक सीजन में खीरे की बुवाई पर मात्र 40 हजार रुपए की लागत आती है।

एक नजर इस पर भी

खेती का समय: इसकी बोवनी फरवरी व मार्च के महीने में की जाती है। बारिश के समय इसकी बुवाई जून-जुलाई में करते हैं।
तैयार करें खेत: खेत को तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। वहीं देशी हल से 2-3 जुताई कर देनी चाहिए। इसके साथ ही 2-3 बार पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाएं और फिर खेत को समतल कर दें।

बोवनी की विधि: बोवनी के दौरान कतार से कतार 5 फीट, दो पौधों के बीच में 2.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके बीज को खेत में सीधे या फिर 8 से 10 दिन के पौधे तैयार करके भी लगाया जा सकता है। खेत में बीजों को एक सेंटीमीटर गहराई में बोया जाता है। पौधे फैलने के बीच में 50 से 100 सेंटीमीटर की दूरी रखना जरूरी है।

किसान मोहन सिंह की जुबानी

मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पिता और भाई के साथ गांव में ही परंपरागत खेती करने लगा। हर साल सोयाबीन की फसल खराब हो रही थी। गेहूं, चना की फसल से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। 10 साल पहले क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तभी से विकल्प की तलाश करने लगा। दो साल तक अलग-अलग फसलें प्रयोगिक तौर पर लगाई। शुरुआत में कई जगह जाकर बागवानी, सब्जी की खेती व फूलों की खेती देखी। इसी दौरान उद्यानिकी विभाग के संपर्क में आया। विभाग की ओर से मुझे तकनीकी खेती और बागवानी करने का सुझाव मिला। इसके बाद मैंने खेत में बगीचा लगाया। साथ ही, टमाटर की खेती शुरू कर दी। हालांकि मैं बागवानी में सफल नहीं हो पाया। दो साल में सभी पेड़ को खराब होने से हटाना पड़ा, लेकिन टमाटर की खेती में सफल हो गया।

तुड़ाई के बाद करते हैं खीरे की पैकिंग

तुड़ाई के बाद खीरे की पैकिंग की जाती है। फिर व्यापारी इसे खरीदकर ले जाते हैं। सब्जी की खेती करने से आमदनी लगातार बढ़ने लगी थी। इसी दौरान खीरा की खेती करना शुरू किया। ड्रिप-इरिगेशन के माध्यम से पहले साल 2015 में खीरा लगाया। शुरुआत से ही अच्छी आमदनी होने के बाद लगातार हर साल खीरा की खेती कर रहा हूं। वहीं, पास में भी टमाटर की खेती के अलावा और भी कई सब्जियां उगा रहा हूं। पहले-दूसरे साल में ही अन्य सब्जियों के मुकाबले खीरा और टमाटर की खेती से अच्छा खासा मुनाफा होने के संकेत मिलने लगे। फिर क्या था। हमने खीरे पर फोकस किया। टमाटर की खेती भी करता रहता हूं, लेकिन खीरा की पैदावार लागत से 5 गुना अधिक मुनाफा है।

ड्रिप व मल्चिंग विधि से खेती का लाभ

जमीन में एक बार ड्रिप लगा देने के बाद पानी देने में परेशानी नहीं आती। साथ ही, कम पानी के बाद भी खेती की जा सकती है। ड्रिप के माध्यम से डाली गई खाद और दवाइयां सीधे पेड़ की जड़ में पहुंच जाते हैं। जबकि मल्चिंग (पन्नी) डालने से कई लाभ हैं। इससे खरपतवार का बचाव, जमीन में रोग नहीं लगते, कीटों का प्रकोप कम, अच्छी ग्रोथ, पौधों की उम्र अधिक हो जाती है। जड़ से संबंधित बीमारियां नहीं लगतीं, अतिवृष्टि होने पर पेड़ खराब होने का खतरा नहीं रहता।

30 दिन में उत्पादन शुरू

बीज रोपाई के 40 से 60 दिन में खीरा का उत्पादन शुरू हो जाता है। इसमें शुरुआत से ही एक जैसा उत्पादन होता है। एक एकड़ में 10 क्विंटल खीरे की फसल ले रहे हैं। इसे तोड़ने के लिए हर दिन तीन लोगों की जरूरत पड़ती है। प्रतिदिन काम करने वाले मजदूरों की 600 रुपए की मजदूरी दी जाती है। खीरे की फसल करीब दो महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, फिर कई महीनों तक फसल देती रहती है।

एक एकड़ में 200 ग्राम बीज

खीरा की खेती के लिए काफी कम बीज की आवश्यकता होती है। एक एकड़ में केवल 200 ग्राम बीज ही बोया जाता है। अच्छी किस्म का 200 ग्राम बीज 5 हजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसकी किस्म बीएनआर-कृस सबसे अच्छी मानी जाती है। खीरे के बेल में बीमारी का खतरा कम रहता है। इसके पत्तों में सफेद फफूंदी रोग लगती है, जिसे डाउनूमील्डू कहा जाता है। इसके अलावा मच्छर थिम्स व इल्ली का काफी कम प्रकोप ही रहता है।

ड्रिप विधि से ज्यादा उत्पादन

मोहन सिंह कहते हैं कि सामान्य खेती से सब्जियों में नुकसान होते हैं। साथ ही, आमदनी भी कम होती है, लेकिन ड्रिप और मल्चिंग विधि से खेती करने पर आमदनी बढ़ सकती है। एक एकड़ में 40 हजार रुपए की ड्रिप व मल्चिंग लगवाई है। इसी तरह से तीन एकड़ में ड्रिप डलवाने में 1.20 लाख की लागत है, जबकि मल्चिंग की 15 हजार रुपए की लागत आई है। हालांकि इस सामग्री में से कुछ हॉर्टिकल्चर विभाग ने अनुदान पर दिया है।

किसानों के लिए खुशखबरी: अब खेती बनेगी लाभ का धंधा

रासायनिक के बजाय प्राकृतिक पद्धति से होगी फसलों की सुरक्षा

'ब्रह्मास्त्र' और 'बीजामृत' रबी खरीफ फसल के लिए संजीवनी

» इंदौर के सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में हो रहा प्रमाणीकरण

» सोयाबीन में फफूंद की समस्या से निजात दिलाएगा बीजामृत

» तीन से पांच वर्षों में इन तकनीकों का प्रमाणीकरण हो सकेगा

इंदौर। जागत गांव हमार

गेहूं, चना, सरसों व सोयाबीन के उत्पादन में अधिकांश किसान अभी तक रासायनिक उर्वरक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर तैयार की जा रही फसलों के कारण जहां मृदा के पोषक तत्व खत्म होने से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। वहीं हानिकारक पेस्टीसाइड का मनुष्यों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नुकसान भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब इंदौर स्थित भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्रप्रदेश के कुछ इलाकों में उपयोग की जा रही बीजामृत, जीवामृत, अब ब्रह्मास्त्र प्राकृतिक पद्धति से की जा रही खेती के तरीकों का प्रमाणीकरण करने की कवायद की जा रही है। इससे भविष्य में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती में इनका उपयोग कर सकेंगे।

फफूंद की नहीं होगी समस्या- सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर ने प्राकृतिक पद्धतियों के कृषि में उपयोग के प्रमाणीकरण के प्रोजेक्ट को जून माह में शुरू किया है। तीन से पांच वर्षों में इन तकनीकों का प्रमाणीकरण हो सकेगा। सोयाबीन की फसल में फफूंद लगना बड़ी समस्या है। बोवनी से पहले बीज को 'बीजामृत' में डालकर बोने से यह समस्या नहीं हो सकेगी। बीजामृत तैयार करने के लिए गिर नस्ल की देशी गाय के 5 किलो गोबर को कपड़े में बांधेंगे और एक ड्रम में 25 लीटर पानी डालकर गोबर बांधे हुए कपड़े को 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे।

'जीवामृत' देगा पोषक तत्व

जीवामृत तैयार करने के लिए एक डिब्बे में 200 लीटर पानी लेना है। उसमें 10 किलो गोबर और उसमें पांच से दस लीटर गिर गाय का गौमूत्र डालें। उसमें दो किलो गुड़, 2 किलो बेसन, एक मुट्ठी मिट्टी डालकर उसे लकड़ी की सहायता से पूरे घोल को हिलाएं। इसे 48 घंटे के लिए ढंककर छोड़ दें। 12 घंटे के अंतराल के बाद इस घोल को पुनः हिलाएं। अब यह घोल फसल पर छिड़काव के लिए तैयार है। सोयाबीन की फसल में यह पोषक तत्व के रूप में काम करेगा। 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर यह घोल मिलाकर छिड़कने से फसल में पोषक तत्वों की कमी पूर्ण हो जाएगी।

बनाने की विधि

किसान कपड़े से बांधे गोबर को निचोड़कर निकालेंगे। अब बचे पानी में पांच लीटर गौमूत्र और 50 मिलीलीटर चूना का पानी डालेंगे। उसमें पीपल या बरगद के पेड़ नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी जिसमें रसायन न हो, उसे मिलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इस तरह बीजामृत घोल तैयार हो जाएगा। सोयाबीन के बीज की बोअनी करने से पहले उसे बीजामृत में डुबोकर बाहर निकालें व बोवनी यंत्र से खेत में बोवनी करें।

कम पानी वाले क्षेत्र घन-जीवामृत का करें उपयोग

जिन इलाकों में पानी की कमी है, वहां जीवामृत के बजाय घनजीवामृत का उपयोग किया सकता है। एक हेक्टेयर खेत के लिए घनजीवामृत को इस तरह तैयार किया जा सकता है। देशी गाय का 500 किलो गोबर लेकर उसे छायादार जगह पर फैला दें। इसमें 20 लीटर जीवामृत का तैयार घोल छिड़क कर मिलाएं। उसके ढेर को इकट्ठा कर 48 घंटे के लिए छोड़ दें। उसे जूट के बोरे से ढंक दें। जब यह सूख जाए तो इसका खेत में खाद के रूप में उपयोग करें।

कीड़ों को नियंत्रित करेगा आग्नेयास्त्र

फसलों में कीड़े लगने की समस्यां के निराकरण के लिए आग्नेयास्त्र व ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। आग्नेयास्त्र को तैयार करने के लिए पांच किलो नीम की पत्ती, एक किलो तंबाकू की पत्ती, आधा किलो तीखी हरी मिर्च, आधा किलो लहसुन को मिलाकर चटनी की तरह पेस्ट बनाएं। उसे 25 से 30 लीटर देशी गोमूत्र में डालें और उसे मटके में गर्म आंच पर झाग आने तक उबालें। अब तैयार घोल को 24 घंटे के लिए छोड़ दें। छानकर घोल निकाल लें, यह स्प्रे के लिए तैयार है।

गौ-मूत्र काफी उपयोगी

एक हेक्टेयर खेत में 12 से 16 लीटर इस घोल को 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर का उपयोग किया जा सकता है। यह घोल पत्तीबेधक, रस चूसने वाले कीड़े और इल्ली को नियंत्रित करता है। इसी तरह ब्रह्मास्त्र के घोल को तैयार करने के लिए 2-2 किलो की मात्रा में नीम की पत्ती, करंज, मकवई, धतूरा, सीताफल, बेलपत्र, अरंडी की पत्तियों मिलकर चटनी की तरह पेस्ट बनाएं और उसे 20 लीटर गौ-मूत्र में मिला दें।

छानकर रस को निकालें

धीमी आंच पर मटके में रखकर एक घंटे तक उबालें और झाग आने तक ढंककर रखें। 48 घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़े व इसे सुबह व शाम को हिलाएं। इसे छानकर रस को निकाल लें। इस तरह यह घोल भी तैयार है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्रप्रदेश के किसान रबी व खरीफ की फसलों में प्राकृतिक खेती के तरीकों को इस्तेमाल वर्षों से करते आ रहे हैं। वे रासायनिक उर्वरक के स्थान पर गौमूत्र, गोबर व अन्य प्राकृतिक चीजों से घोल तैयार करते हैं। किसानों के अनुभव से प्राकृतिक कृषि की तकनीकों का हम अगले तीन से पांच साल में वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणीकरण करेंगे। इससे भविष्य में ज्यादा से ज्यादा किसान इन प्राकृतिक पद्धतियों का कृषि कार्य में उपयोग कर सकेंगे।

-डॉ. राघवेंद्र नरगुंद, वैज्ञानिक, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर

खेती-किसानी को उन्नत बनाने के उपायों की तलाश के लिए तीन दिनी कार्यशाला

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार राज्य में खेती-किसानी को उन्नत बनाने के लिये सतत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में 22 से 24 अगस्त को किसान-कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा डब्ल्यू.आर.आई. इण्डिया और फूड एण्ड लेण्ड यूज कोलिशन (फोलू) इण्डिया के सहयोग से कार्यशाला की गई। कार्यशाला में कृषि को उन्नत बनाने के सर्वश्रेष्ठ उपायों की तलाश की गई। आयुक्त कृषि एम. सेलवेन्द्रन, एमडी मण्डी बोर्ड श्रीमन शुक्ला, डब्ल्यू.आर.आई इण्डिया की निदेशक डॉ. रुचिका सिंह, फोलू इण्डिया के कंट्री को-ऑर्डिनेटर डॉ. जयहरि के.एम., विभिन्न संगठनों के सदस्य और कृषि विभाग के 150 से अधिक अधिकारी शामिल हुए।

आयुक्त कृषि सेलवेन्द्रन ने कहा कि पूरे देश में सतत और उन्नत कृषि पद्धतियों के सफल मॉडल्स का परीक्षण करना और विशेष रूप से मध्यप्रदेश के लिये सर्वाधिक उपयुक्त पद्धतियों की पहचान करना कार्यशाला का उद्देश्य है। इन मॉडल्स में कृषि मूल्य श्रृंखला से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यशाला में प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती के रकबे को बढ़ाने के लिये किसानों को देशी गाय के पालन के लिये 900 रूपये अनुदान दे रही है। कार्यशाला में सिविल सोसायटी संगठनों, खाद्य एवं कृषि से जुड़े निजी संगठनों के साथ-साथ फोलू इण्डिया को प्रमुख साझेदारों के रूप में शामिल किया गया है। एमडी मण्डी बोर्ड शुक्ला ने कहा कि विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की सहभागिता से कृषि को उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी। संगठनों ने भी अपने प्रेजेंटेशन दिए।

खाद्य सुरक्षा और पोषण संभावनाओं को दूर करने के लिए शहरी बागवानी का महत्व

मोहन लाल जाट
जितेंद्र सिंह शिवरान
ओमप्रकाश कुमावत
-चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
-गोबिंद पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड
-महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान

हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन और शहरी इलाकों में स्थायी खाद्य आपूर्ति की इच्छा के कारण शहरी कृषि में रुचि बढ़ी है। शहरी बागवानी ने कोविड-19 जैसी महामारी संबंधी बीमारियों के दौरान अपना महत्व बढ़ा दिया है, जिसने विश्व स्तर पर खाद्य असुरक्षा को जन्म दिया है। 2050 तक अनुमानित 10 बिलियन लोगों में से लगभग 70 प्रतिशत लोग शहरों में रहने का अनुमान किया जा सकता है। एक चौंका देने वाला विषय और एक स्थायी खाद्य भविष्य की कल्पना करते समय इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में शहरी बागवानी की भूमिका पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

आधुनिकीकरण और शहरीकरण के चलते आधिकारिक तौर पर विकास होता जा रहा है और शहरी क्षेत्र बढ़ते हुए जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए बेहद आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या और रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर जा रहे हैं लेकिन शहरों में उनको ताजे फल और सब्जी ली मांग पूरी नहीं हो पा रही है जनसंख्या के सामने भोजन और पोषक तत्वों की समस्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए शहरी बागवानी एक समाधान प्रदान कर सकती है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी संभावनाओं को सुधारने में सहायता करती है।

हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन और शहरी इलाकों में स्थायी खाद्य आपूर्ति की इच्छा के कारण शहरी कृषि में रुचि बढ़ी है। शहरी बागवानी ने कोविड-19 जैसी महामारी संबंधी बीमारियों के दौरान अपना महत्व बढ़ा दिया है, जिसने विश्व स्तर पर खाद्य असुरक्षा को जन्म दिया है। इसके अलावा, उच्च गरीबी दर, कुपोषण, अवरुद्ध विकास और दुनिया भर में बढ़ती आबादी ने शहरी बागवानी के महत्व को बढ़ा दिया है। लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शहरी क्षेत्रों में खाली स्थान एक प्रमुख प्राथमिकता होगी ताकि भूमि को बंजर छोड़ दिए जाने पर भोजन की कमी और शहरी पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई की जा सके। शहरी परिदृश्यों और खुले स्थानों में बागवानी खाद्य फसलें उगाने से भोजन और पर्यावरण की स्थिरता में सुधार होगा। शहरी बागवानी, मूलत सामाजिक सामाजिक चुनौतियों को कम करने का एक तरीका है इस लेख में हम शहरी बागवानी के महत्व को देखेंगे और खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए इसके संभावना को समझेंगे।

शहरी बागवानी का महत्व: शहरी बागवानी शहरी इलाकों में खेती का एक रूप है जिसमें वनस्पति पौधों, फूलों और सब्जियों की खेती की जाती है। यह एक शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वदेशी और स्वयंनिर्भर बनाने में मदद करता है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कारणों से शहरी बागवानी खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए महत्वपूर्ण है-

स्वयं की खाद्य सुरक्षा: शहरी बागवानी नगरीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुधारती है। लोग अपने खुद के बगीचे में सब्जियां और फल उगा सकते हैं, जिससे खाद्य संसाधनों का संरक्षण होता है और नागरिकों को भोजन की सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ये ताजा सब्जिया और फल की पूर्ति भी हो जाती है।

पोषण संभावनाएं सुधारना: शहरी बागवानी विभिन्न प्रकार के स्वस्थ और पोषण से भरपूर पौधे उगाने में मदद करती है। बहुत सारी सब्जिया विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है, जिनमे बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं।

पर्यावरण का संरक्षण: शहरी बागवानी शहर की हरियाली को बढ़ावा देने में मदद करती है और शहर के वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने में मदद करती है। पौधों के सँक्षेप में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने से पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है। इसके साथ वाहनों से निकलने वाले धुए को अवशोषित करने में सहायता करता ह लेकिन पादपो का चयन ध्यान में रखना चहिये।

खाद्य संसाधनों के जलवायु पर प्रभाव: शहरी बागवानी शहरों में वन्य भूखंडों की अवस्था को बेहतर बनाने में मदद करती है जिससे खाद्य संसाधनों के जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्राकृतिक वायुमंडल को बढ़ावा देती है जो वन्य प्राणियों और पौधों के लिए अनिवार्य है।

गरीबों को रोजगार का अवसर: शहरी बागवानी गरीब और निम्न-आय वाले लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। वे अपने छोटे भूखंडों में फल और सब्जियां उत्पादित करके उन्हें बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इससे उन्हें खाने के लिए स्वदेशी और स्वदेशी उत्पादों का उचित उपयोग करने में सक्षम बनाने में मदद मिलती है।

शहरी बागवानी खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक प्रोमिनेंट समाधान है। यह खुद की खेती का अवसर प्रदान करती है और लोगों को स्वदेशी खाद्य स्रोतों का उपयोग करने में मदद करती है। इसके माध्यम से, लोग अपने खुद के उत्पाद का उपभोग कर सकते हैं, जो उन्हें स्वयंनिर्भर बनाता है। इसके अलावा, शहरी बागवानी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है और वनस्पति के संचय के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। इसलिए, हमें शहरी बागवानी के महत्व को समझते हुए, इसे बढ़ावा देना और इसके पोटेंशियल को समझना चाहिए। इससे हम खाद्य सुरक्षा और पोषण को सुधार सकते हैं और समृद्ध और स्वस्थ नगरीय क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं।

धान की पैदावार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन

हर्ष गुप्ता
मृदा विज्ञान, कृषि संकाय, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना म.प्र.

भारत में दुनिया के कई देशों के मुकाबले, धान की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन काफी कम है और इसका एक प्रमुख कारण पोषक तत्वों का समय से सही प्रबंधन ना होना है। वैश्विक रूप में, यदि सही ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन नहीं किया जाता तो धान की फसल में सालाना उत्पादन में 10 से 15 फ़ीसदी की कमी होने का अनुमान है। ऐसे में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए सही समय पर पोषक तत्व प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है। इस विचार में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है क्योंकि यह पौधे को सही पोषण प्रदान करके, पौधों की स्वास्थ्य बनाने में तथा विकास और पैदावार में सुधार करने में सहयोग करता है।

पौधे के विकास के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा अति आवश्यक होती है और यह पोषक तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति उर्वरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। धान की खेती भारत में अधिकतर क्षेत्रों में प्रमुख खरीफ फसल के रूप में की जाती है, जिसकी रोपाई अभी चल रही है लेकिन जिस क्षेत्र में लगातार फसलें ली जाती हैं उसमें सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। आमतौर पर किसान डी.एपी., यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश फसल में देते हैं और बाद में खड़ी फसल में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं जिससे फसल की विकास अवस्था प्रभावित होती है और उत्पादन कम होता है। फसलों के लिए मुख्य 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्राकृतिक रूप से फसलों को कम मिल पाते हैं, जिसकी पूर्ति उर्वरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। मृदा में सल्फर, बोरान, जिंक, आयरन जैसे सूक्ष्म तत्व की मौजूद रहते हैं लेकिन आज उनकी कमी भी मिट्टी में देखी जाती है वहीं अन्य तत्व प्राकृतिक रूप से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं।

धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन: अगर धान की फसल की बात करें तो कई जगह धान की पिछली रोपाई हो रही है और कुछ किसान रोपाई कर भी चुके हैं ऐसे में धान का सही पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए-

पोषक तत्व की उपलब्धता जानने के लिए, मिट्टी की जांच के लिए विशेषज्ञता युक्त प्रक्रिया अनुसरण करें। इसके लिए मिट्टी के नमूने को, खेत के विभिन्न स्थानों से कम से कम 15 सेंटीमीटर जगह हटाकर ले और पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस , कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आयरन, जिंक, बोरोन जैसे तत्वों की जांच कराएं। यदि किसान मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो वह धान की रोपाई के समय जिंक सल्फेट छिड़क सकते हैं क्योंकि जिंक तत्व की कमी प्रायः हर जगह देखी जा रही है। सल्फर बोरोन आयरन जैसे सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग मिट्टी की जांच के पश्चात करे।

धान की खड़ी फसल में फसल में जिंक तत्व की कमी के कारण लक्षण रोपाई के 20-25 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। धान में जिंक तत्व की कमी को खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें पत्तियां भूरे एवं लाल रंग की हो जाती हैं या पान की पीक की तरह पत्तियां दिखने लगती हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए किसान आमतौर पर जिंक सल्फेट का छिड़काव कर देते हैं, जिससे इस समस्या का नियंत्रण नहीं होता। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए , 800 लीटर पानी में 2.5 कि.ग्रा. बुझे हुए चुने के साथ 5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट के साथ घोल बनाकर उपयोग करना चाहिए यदि चुना नहीं है तो 20 कि.ग्रा. यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है।

धान में आयरन की कमी को सफेदा रोग के नाम से जानते हैं, इसमें धान की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, 800 लीटर पानी में, 2.5 कि.ग्रा बुझे हुए चूने के साथ 3 कि.ग्रा फेरस सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। सल्फर फसल के लिए अच्छा होता है यह प्रोटीन निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और दानों के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। आमतौर पर मिट्टी में उपलब्ध होता है लेकिन गहन फसल चक्र के चलते, इसकी कमी मिट्टी में हो जाती है। इसलिए रोपाई के समय डी.ए.पी. की जगह एस.एस.पी. का उपयोग करना चाहिए। यदि खड़ी फसल में, नई पत्तियों में पीलापन दिखाई दे तो सल्फर का 3 कि.ग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए । भारी बारिश से बचने के लिए अपने उर्वरकों के प्रयोग का समय निर्धारित करें। भारी बारिश से ठीक पहले उर्वरक लगाने से पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। इन्हें तब लगाएं जब बारिश की उम्मीद न हो या जब मिट्टी पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सके। जल निकायों के पास खेतों के किनारों पर घास या झाड़ियों जैसी वनस्पति की बफर स्ट्रिप्स बनाएं। ये बफर स्ट्रिप्स बहते पानी को फ़िल्टर करने में मदद करती हैं, पोषक तत्वों को जलमार्गों तक पहुंचने से पहले ही रोक लेती हैं। ढलान वाली भूमि पर, पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए छत बनाएं, जिससे मिट्टी को पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए अधिक समय मिल सके।

इन प्रथाओं को अपनाकर, आप भारी बारिश के दौरान पोषक तत्वों की हानि को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित कर सकते हैं और अपनी फसलों और पर्यावरण दोनों की रक्षा कर सकते हैं।

ग्रामीण भारत में मोटे और कुपोषित क्यों हो रहे हैं लोग, अध्ययन में पता चला

इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स के साक्षात्कार आधारित एक नए अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक कार्बोहाइड्रेट और मीठा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनमें प्रोटीन कम पाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग अधिक कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, क्योंकि वे किफायती और अधिक सुविधाजनक हैं। अधिक मीठे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खा रहे है, क्योंकि वे दुकानों में आसानी से उपलब्ध हैं और स्वस्थ फलों और सब्जियों की तुलना में उनकी आयु लंबी होती है।

यह अध्ययन भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य संकट को उजागर करता है, जिसमें ग्रामीण मोटापे और कुपोषण के बढ़ने के कारणों की पड़ताल की गई है।

यह अध्ययन भारत के एक राज्य तेलंगाना के ऑरेपल्ले, डोकुर गांवों और अमंगल और देवारकाद्र कस्बों में आयोजित किया गया था। अध्ययन में कहा गया है कि, यहां लोगों को प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों की तलाश करने की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट और शर्करा युक्त डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हासिल करना अधिक सुविधाजनक लगता है।

आईसीआरआईएसएटी के अध्ययनकर्ता के मुताबिक, अध्ययन प्रोटीन तक लोगों की पहुंच की कमी और पारंपरिक खाद्य प्रणालियों और पोषण आधारित खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आते हैं वे अपना खाना भी बदल देते हैं क्योंकि वे बड़े पैमाने पर डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं।

अध्ययन में कहा गया कि, बाजरा जैसे पौष्टिक उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाकर विरासत को स्वास्थ्य के साथ मिश्रित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

पोषण और परंपरा के बीच संतुलन: अध्ययन के हवाले से कहा गया है कि, आईसीआरआईएसएटी अपने कृषि व्यवसाय नवाचार मंच के माध्यम से और अपने सहयोगियों के साथ किफायती, पौष्टिक उत्पाद विकसित करने और बाजार से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों के बारे में शिक्षित करने का काम कर रहे हैं।

अध्ययनकर्ता ने कहा, हम मोटापे और कुपोषण की खतरनाक वृद्धि से निपटने के लिए ग्रामीण भारत में पारंपरिक खाद्य प्रणालियों की समृद्ध बनाने, पुनर्जीवित करके पोषण और परंपरा के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

अध्ययन में लिए गए साक्षात्कार में तेलंगाना के औरेपल्ले गांव के व्यक्ति ने बताया कि, हम पहले मुख्य रूप से ज्वार खाते थे, जिसकी जगह चावल ने ले ली है क्योंकि यह सस्ता और आसानी से मिल जाता है। हम जंगल से जंगली फल और भोजन भी इकट्ठा करते थे। लेकिन अब उन्हें ढूंढना भी कठिन है क्योंकि वहां जंगल कम रह गए हैं। उन्होंने बताया कि कई समय पहले उनका परिवार ज्वार खाता था लेकिन अब शायद ही कभी इसका उपयोग खाने में करते है।

अध्ययन में कहा गया है कि लोगों को स्थानीय भोजन उगाकर पौष्टिक भोजन के सेवन के बारे में बताना जरूरी है। अध्ययनकर्ता ने कहा, बाजार तंत्र की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझकर, हम एक ऐसा रास्ता तैयार कर सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों को पौष्टिक भोजन के विकल्पों तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगा।

नवाचार गुजरात, महाराष्ट्र ओर चीन में देख जिले में पहली बार 50 से ज्यादा गांवों में की बोवनी

कृषि विभाग ने नागपुर से 7 वैरायटी का बीज मंगाकर बोवनी कराई

500 एकड़ में सघन विधि से लगाया कपास पांच क्विंटल एकड़ तक बढ़ जाएगा उत्पादन

खरगोन। जागत गांव हमार

प्रदेश में खरगोन जिले में सर्वाधिक कपास उत्पादन को देखते हुए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर कृषि तकनीक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत उच्च सघनता उत्पादकता (हाई डेंसिटी प्रोडक्शन) को लेकर कपास बोवनी नवाचार हुआ है। इस साल लगभग 500 एकड़ रकबे में फसल लगाई गई है। किसानों ने 16 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन का लक्ष्य रखा है। गुजरात, महाराष्ट्र व चीन में इस तरह की खेती हो रही है। निमाड़ में खरगोन जिले से यह शुरुआत हुई है। गत वर्ष सीमित संख्या में इस विधि से बोवनी की थी। 12-16 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादकता रही। अब कृषि विभाग यह कार्यक्रम चला रहा है। इसके लिए नागपुर से सात वैरायटी का बीज मंगवाया गया है। उप संचालक कृषि एमएल चौहान का कहना है कि कलेक्टर के निर्देशन में सघन कपास उत्पादकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभाग को उम्मीद है कि यदि किसानों को अच्छा मुनाफा होता है तो अगले कुछ सालों में इसका रकबा तेजी से बढ़ेगा। जिले में लगभग सवा दो लाख हेक्टेयर में बीटी कॉटन की बोवनी होती है। कपास की उत्पादकता बढ़ाने पर किसान इस पद्धति की तरफ तेजी से बढ़ेंगे।

चीन, महाराष्ट्र व गुजरात में देखी तकनीक: महाराष्ट्र गुजरात व चीन में इस तरह की खेती होती है। मोहम्मदपुर के किसान मोहनसिंह सिसोदिया बताते हैं कि जिला मुख्यालय पर 16 जून के किसान सम्मेलन के कृषि तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जानकारी मिली थी। 2021 में राजकोट गुजरात में 15 किसानों के दल ने यह तकनीक देखी थी। वहां 50 फीसदी रकबे में सघन कपास की बोवनी कर रहे हैं। लगभग 17.86 क्विंटल उत्पादकता देखी। चीन में भी ऐसी बोवनी पर वहां कपास की सर्वाधिक कपास उत्पादकता है। प्रति एकड़ 12 हजार पौधे पर 4.80 लाख डेंडू (प्रति पौधा 40 डेंडू) लगते हैं। 4 लाख डेंडू पर 16 क्विंटल उत्पादन होता है।

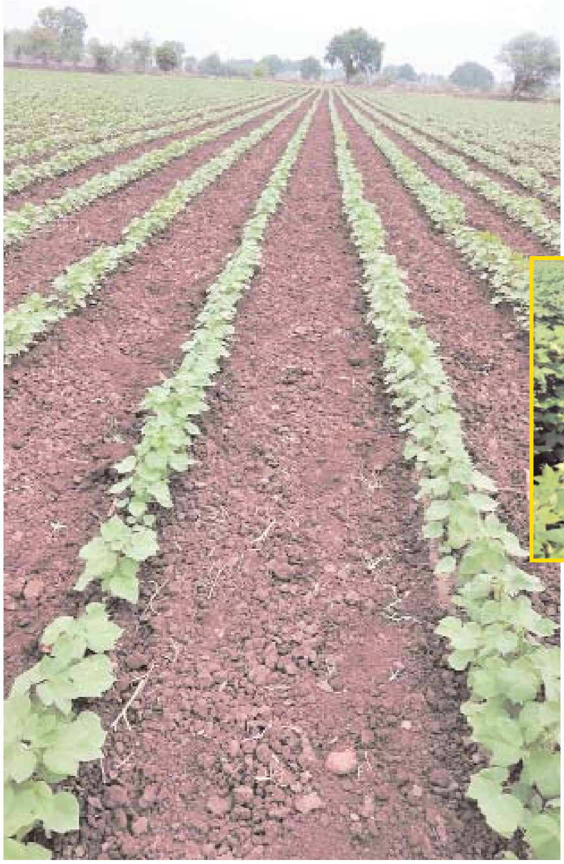

जानिए, क्या है सघन कपास उत्पादकता

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक काम फैलाव व ऊंचाई वाली वैरायटी के ज्यादा मात्रा में पौधों की बोवनी होती है। जिले में कतार की दूरी 90 सेमी व पौधे की दूरी 20 सेमी रखकर बोवनी की गई हैं। एक एकड़ में लगभग 14 हजार पौधे लगते है। 45, 65 व 85 दिन की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर (पीजीआर) करते है, जिससे अच्छी बढ़वार व फ्लोरिंग होती है। क्षेत्र में तीन दशक पहले तक खंडवा-2 व लाल काड़ी का कपास ऐसे ही बोया जाता रहा है। तब मुश्किल से दो-तीन क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादकता होती थी।

चार क्विंटल तक बढ़ती है उत्पादकता

कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. जीएस कुलमी का कहना है कि कपास की हाई डेंसिटी प्रोडक्शन (एसडीपी) खेती महाराष्ट्र व गुजरात में भी होती है वहां 16-23 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिल रहा है। इसमें प्रति एकड़ 4 पैकेट बीज लगता है। जबकि उत्पादकता 4 क्विंटल तक बढ़ जाती है। अभी 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादकता है।

सघन कपास उत्पादकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नागपुर से कृषि अनुसंधान का 7 वैरायटी का कपास बीज लाकर बोवनी की गई है। बेहतर उत्पादन मिलता है तो रकबा और बढ़ेगा।

-एमएल चौहान, उपसंचालक, कृषि खरगोन

मप्र सरपंच संगठन ने की मप्र सरकार से मांग

प्रदेश की पूर्व सरपंचों को मिले लाड़ली बहना योजना का लाभ

भोपाल। जागत गांव हमार

पूर्व सरपंचों को लाड़ली बहना योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सरपंच व उनके आश्रितों के कल्याण को देखते हुए यह मांग है मप्र सरपंच संगठन की। प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यानआकर्षित करते हुए कहा कि जब सरकार संविदा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से व्यक्तियों की आर्थिक चिंता कर रही है तब पूर्व सरपंच क्यों नजर अंदाज किए जा रहे हैं।

इससे पहले उन्होंने कहा कि सरपंच को मात्र 4250 रूपये मानदेय के रूप में दिया जाता है। जनप्रतिनिधि का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह राशि मिलनी बंद हो जाती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व जनप्रतिनिधियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। एक सवाल के जबाव में उन्होंने यह स्वीकार किया कि नियमों की विसंगतियां ग्राम विकास को न केवल बाधित कर रही है, बल्कि जनप्रतिनिधियों के प्रति ग्रामीणों के बीच विद्वेष का कारण भी बन रही है। वजह यह भी है कि स्वावलंबी ग्राम बनाने के लिए सरकार ने पंचायतों को राजस्व जुटाने का दबाव बनाया है। बावजूद इसके करारोपण के दूसरे माध्यमों (रेत और खनिज, वन संपदा) से सरकार दूसरे विभागों के माध्यम से सीधे राजस्व वसूल रही है।

चरनोई के लिए नहीं बची सरकारी भूमि

ग्रामीण क्षेत्र में गौवंश के चारे के लिए सरकार द्वारा आरक्षित अब कोई भूमि नहीं बची है। सरपंच संगठन ने भविष्य के मद्देनजर इसकी जरूरत मानते हुए सरकार को उचित कदम उठाने की मांग की है। साथ की कहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को मिले 29 अधिकार बहाल किए जाएं। साथ ही जनपदों में बैठने के लिए सरपंच को कक्ष की मांग दोहराते हुए सरकार से जून 2022 से लंबित प्रधानमंत्री आवास व आवास प्लस की राशि स्वीकृत करने के लिए कहा है।

महिलाओं के नेतृत्व पर जोर दिया

महिला पंचायत पदाधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित

भोपाल। जागत गांव हमार

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली एवं अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण 23 अगस्त को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में आयोजित किया गया।

राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव तृप्ति राज त्रिपाठी द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी तथा प्रतिभागियों को जन-प्रतिनिधियों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने की अहमियत के बारे में बताया। जीपी अग्रवाल ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एव उसमे महिलाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी सत्र के दूसरे दौर में अमित खरे, एएसपीएम, मप्र राज्य आजीविका मिशन द्वारा आजीविका संवर्धन के अहम पहलुओं पर चर्चा की। सुनील वर्मा, सहायक संचालक, जनसंपर्क ने संचार कौशल एवं सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग का महत्व बताया। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में एमएल त्यागी ज्वाइंट कमिश्नर मनरेगा ने योजना के बेहतर क्रियान्वन में पंचायतों की भूमिका एवं महिलाओं के नेतृत्व पर जोर दिया।

-आत्मनिर्भरता के लिए पहलः मप्र में अब ड्रोन से खेती किसान

अक्टूबर-नवंबर तक किसानों के खेतों उड़ते नजर आएंगे ड्रोन

भोपाल।

अब जल्द ही प्रदेश के खेतों में आपको ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देंगे। किसान ड्रोन से खेती करेंगे। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को ड्रोन दिलाए जाने के लिए कृषि अभियांत्रिकी ने आवेदन बुलाना भ्री कर दिए हैं। अक्टूबर-नवंबर तक मध्यप्रदेश के किसान ड्रोन से खेती करते नजर आएंगे। 9 से 10 लाख तक का ड्रोन किसानों को ढाई से 5 लाख तक में मिलेगा। किसानों को नई तकनीक में दक्ष बनाने और खेती में उन्नत करने के लिए ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन से खेती करने में किसानों को समय की बचत होगी और दस दिन में होने वाला काम एक ही दिन में हो जाएगा। किसानों को ड्रोन पर 4 लाख से 7 लाख 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी सरकार देगी। अभी एक ड्रोन की कीमत 9 ला लाख 24 हजार से 9 लाख 90 हजार रुपए तक है। ड्रोन खरीदी के लिए अब तक कृषि संचालनालय के पास 150 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कृषि अभियांत्रिकी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन के लिए आवेदनों की पहले पात्रता जांची जाएगी। इसके बाद किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के किसानों को ड्रोन दिए जाने का यह पहला प्रोजेक्ट है। इसके लिए संचालनालय ने पांच कंपनियों से अनुबंध कर लिया है। इन कंपनियों से किसान सीधे बात करके ड्रोन खरीद सकते हैं। इसके बाद सब्सिडी सरकार देगी। ड्रोन लेने वाले किसान को दसवीं पास होना भी जरूरी है।

ड्रोन पायलेट का लायसेंस मिलेगा

ड्रोन लेने के लिए किसानों को ड्रोन पायलेट का लायसेंस लेना जरूरी है। किसानों को ड्रोन का लायसेंस और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा की गई है। ड्रोन का लायसेंस और प्रशिक्षण का शुल्क 30 हजार रुपए है। प्रशिक्षण का 50 फीसदी यानी 15 हजार रुपए कृषि अभियांत्रिकी विभाग देगा। शुल्क का 50 फीसदी हिस्सा किसानों को देना होगा। ड्रोन चलाए जाने का प्रशिक्षण 7 दिन का रहेगा। इसके लिए संचालनालय ने इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी अमेठी से करार किया है। यह एकेडमी किसानों को ड्रोन चलाना सिखाएगी और लायसेंस भी देगी। इसके अलावा ड्रोन लेने के लिए किसानों को पासपोर्ट लेना भी लेना होगा।

बैटरी चलने वाले होंगे ड्रोन

संचालनालय के अधिकारियों के मुताबिक किसानों को दो प्रकार के ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बैटरी से चलने वाला ड्रोन और दूसरा पेट्रोल से चलने वाला ड्रोन। बैटरी से चलने वाला ड्रोन दो घंटे में चार्ज होता है। इसके बाद ड्रोन 15 मिनट तक उड़ सकता है। 15 मिनट की उड़ान में ड्रोन डेढ़ एकड़ खेत में खाद या दवाई का छिड़काव कर सकता है। इसकी ज्यादा उड़ान लेने के लिए किसानों को अतिरिक्त बैटरी रखना होंगी। इसके अलावा पेट्रोल से चलने वाला ड्रोन भी 15 मिनट की एक उड़ान भरेगा। एक उड़ान के बाद उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसके बाद उसे दोबारा पेट्रोल डालकर उड़ान के लिए तैयार किया जा सकेगा। ये दोनों विकल्प किसानों के पास उपलब्ध रहेंगे। किसान ड्रोन का मु य उपयोग फसलों पर दवा और ज्यादा छिड़काव में कर सकेंगे।

किसानों को मिलेगी सब्सिडी

ड्रोन खरीदने वाले किसानों को तीन वर्गों में सब्सिडी मिलेगी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50 फीसदी अधिकतम 5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्ग के कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालकों के लिए 40 फीसदी अधिकतम 4 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कृषक उत्पादक संगठन के अंतर्गत 75 फीसदी अकिधतम 7 लाख 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात में कारखाने की रख चुके नींव

नैनो यूरिया के बाद अब नैनो लिक्विड डीएपी बनाएगा इफको

» 50 किलो खाद की जगह किसान केवल आधा लीटर डीएपी इस्तेमाल करेंगे

» यह प्लांट 70 एकड़ के एरिया में बनेगा और महज एक साल में पूरा होगा

भोपाल।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीधाम में देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए इफको के लिक्विड नैनो डीएपी प्लांट की नींव रखी है। इस प्लांट की खासियत यह होगी कि 50 किलो फर्टिलाइजर की जगह किसान केवल आधा लीटर तरल फर्टिलाइजर अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। यह प्लांट 70 एकड़ के एरिया में बनेगा। महज एक साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इफको के इस प्लांट के बनने के बाद आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस नैनो फर्टिलाइजर प्लांट से इफको उचित मात्रा और उचित दाम में भारत के किसानों को खाद की सप्लाई करेगा। यह दुनिया का पहला लिक्विड नैनो डीएपी बनाने वाला प्लांट है। शाह ने कहा कि जब सहकारिता मंत्रालय बना तो सहकारिता से समृद्धि का मंत्र पीएम मोदी ने हमें दिया। लिक्विड नैनो डीएपी से हमारी धरती माता संरक्षित होगी, उसमें जहर नहीं जाएगा। किसान धरती की उर्वरता कम होने का चैलेंज फेस कर रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। इस खाद से पानी भी दूषित नहीं होगा, सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा, सरकार आत्मनिर्भर बनने दिशा में आगे बढ़ेगी। भारत को दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। प्राकृतिक खेती की हरित क्रांति करनी है, जो आर्गेनिक प्रोडक्ट भारत का किसान उत्पादन करेगा, वो दुनिया भर से संपत्ति भारत में लाएगा।

दलहन-तिलहन होंगे आत्मनिर्भर

शाह ने कहा कि दलहन और तिलहन के मामले में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्राकृतिक खेती से उपजे उत्पादों का उचित मूल्य किसान को देना सबसे जरूरी है। अच्छे ब्रांड के साथ विश्व के बाजारों को किसानों के प्रोडक्ट भेजे जाएंगे। छोटे से छोटे किसान को अपने प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार में उतारने का मौका मिलेगा। सहकारिता के जरिये ये नई हरित क्रांति की अहम कड़ी है। 350 करोड़ रुपए की लागत से 70 एकड़ के एरिया में ये प्लांट बनेगा। तरल नैनो डीएपी संयत्र में इफको अपना पैसा लगाएगा।

हर खाद में देश आत्मनिर्भर बनेगा

अमित शाह ने कहा कि हर तरह की खाद में देश आत्मनिर्भर बनेगा। एक साल के भीतर ही ये तरल डीएपी का कारखाना डीएपी का उत्पादन करेगा इस प्लांट को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया है। यह प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर भारत के किसानों के लिए मजबूत पिलर है और आज ये पिलर ज्यादा मजबूत होगा। मोदी सरकार ने पैक्स को मल्टी-डायमेंशनल बनाया है।

-सिहोरा के सियाराम वेयर हाउस में रखी मूंग भी जांच होगी

जांच में देखा जाएगा कि मूंग इसी सीजन की या फिर पुरानी

सियाराम वेयरहाउस की मूंग का होगा सत्यापन

जबलपुर।

सिहोरा के पास स्थित सियाराम वेयर हाउस में पाई गई खामी की गहन पड़ताल जारी है। पोर्टल पर दर्ज आकड़े के मुकाबले कम मात्रा में मूंग पाए जाने का खुलासा तो पहले ही हो चुका था। अब प्रशासन की ओर से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वहां जो मूंग उपलब्ध है- उसकी गुणवता कैसी है। वह इसी सीजन की खरीदी हुई मूंग है या फिर उसे कहीं और से लाकर यहां रखवाया गया है। इसे लेकर सवाल छापामारी के बाद से ही उठ रहे हैं। वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक सखाराम निमोदा ने बताया कि सियाराम वेयर हाउस में इस वक्त रखी मूंग की भी जांच कराई जाएगी। इस जांच में देखा जाएगा कि मूंग इसी सीजन की है या फिर पुरानी। प्रथमदृष्टि में मूंग के अमानक होने के संकेत मिल रहे हैं। इसे ही आधार बनाकर मूंग का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।

भोपाल से आएगी टीम

वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन के भोपाल कार्यालय से एक टीम जबलपुर आ रही है, जो मूंग की गुणवत्ता को जांचेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। समझा जाता है कि इस जांच से कुछ ऐसे नए तथ्य सामने आ सकते हैं जो नए राज खोल सकते हैं। इधर सूत्रों का कहना है कि मूंग में बड़े पैमाने पर घुन लगी हुई है, जो इस सीजन की नहीं महसूस हो रही। इस मूंग को कथित तौर पर खरीदी समाप्त होने के बाद गोदाम में रखवाया गया है।

यह रहा मामला

कलेक्टर के निर्देश पर एक जांच दल ने सियसराम वेयर हाउस का निरीक्षण किया था। वहां 40 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी पोर्टल पर शो हो रही थी। लेकिन वास्तव में वहां 32 हजार क्विंटल मूंग ही ही मिली थी। 80 क्विंटल कहां गई, इस बारे में वेयर हाउस संचालक के पास कोई जवाब नहीं रहा। जिस पर पुलिस में एफआइआर भी दर्ज की गई।

एक बड़ा सवाल

इस मामले में सिहोरा की वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स मैनेजर लक्ष्मी ठाकुर को भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। उनका नाम एफआइआर में नहीं दर्ज कराया जाना संदेह को जन्म दे रहा है। वेयरहाउस में उपार्जन का काम देख रहे एफपीओ की मुखिया परोक्ष रूप से लक्ष्मी ठाकुर ही रहीं। इसी तरह का एक मामला करीब डेढ़ महीने पहले चरगवां में भी देखने में आया था। वहां मयंक वेयर हाउस में गड़बड़ी के बाद एफआइआर तो कराई गई थी, लेकिन एफपीओ में जिन प्रभावशाली लोगों का दखल रहा, उनका नाम कहीं नहीं आया था। वहां के एफपीओ में एक सेवानिवृत्त खाद्य अधिकारी की पत्नी डायरेक्टर मंडल की सदस्य रही।

नाफेड ने भी उठाए थे सवाल

नाफेड ने भी खरीदी के दौरान ही जिले के विभिन्न खरीदी केंद्रों की जांच कराई थी, उस दौरान 14 केन्द्र ऐसे मिले थे, जहां की मूंग गुणवत्ताविहीन रही। लेकिन बाद इन केन्द्रों की सूची को ही दबा दिया गया था। इधर भुगतान की प्रक्रिया चलती रही। नाफेड की टीम ने जिन वेयर हाउसों में निम्न गुणवत्ता की मूंग बताई थी उनमें श्रीराज वेयर हाउस बेगमगंज, हिमांशु वेयर हाउस बघेली, मां रेवा वेयर हाउस शेरपुर, अनुश्री वेयर हाउस क्षिप्रा फर्मस कम्पनी, ठाकुर वेयर हाउस मुर्रई, मधुर शिवम वेयर हाउस, उत्तम ज्योति वेयर हाउस तेवर, भाग्यवती वेयर हाउस तेवर, दद्दा वेयर हाउस मझौली, मैना वेयर हाउस बरखेड़ा, एमपीडब्ल्यूएलसी-02 बुढ़ागर, आदि एवं बालाजी वेयर हाउस वृहताकार सहकारी समिति शामिल हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की वार्षिक साधारण सभा संपन्न

318 करोड़ 18 लाख का बजट पारित, 2023-24 में 16 करोड़ 50 लाख रुपए के मुनाफे का टारगेट

प्रदेश की प्रथम संस्था घुघरियाखेड़ी के पेस्टीसाईट छिड़काव ड्रोन का हुआ लोकार्पण

बैंक अपनी सदस्य संस्थाओं को 1.50 प्रतिशत की दर से तीन करोड 80 लाख रुपए का लाभांश देगी

संजय शर्मा। खरगोन

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की वर्ष 2022-23 की वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक 20 अगस्त 2023 को राधाकुंज परिसर में संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2023-24 का 318 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। 16 करोड़ 50 लाख रुपए के मुनाफे का लक्ष्य रखते हुए 2864 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस संबंध में बैंक के एमडी राजेन्द्र आचार्य द्वारा बताया गया कि प्राथमिक कृषि साख संस्था घुघरियाखेड़ी को नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से प्राप्त ड्रोन जिससे पेस्टीसाईट छिड़काव होगा उसका लोकार्पण कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा एवं अपेक्स बैंक भोपाल के एमडी पीएस तिवारी द्वारा किया गया। राजेन्द्र आचार्य एमडी बैंक ने सभा में अवगत कराया कि वर्ष 2022-23 में बैंक ने तकनीकि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, बैंक राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र की बैंकों के समकक्ष खड़ी हो चुकी है। बैंक की अंशपूंजी में गत वर्ष की तुलना में 2.14 करोड़ की वृद्धि हुई है। अमानतों में 236.13 करोड़ रुपए और कार्यशील पूंजी में 144.49 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की है। बैंक के कृषि ऋणों की वसूली 77.02 प्रतिशत हुई है। यही कारण है कि अलोच्य वर्ष के दौरान बैंक ने 16.47 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

जिला सहकारी बैंक के नवाचार

ड्रोन के संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अनिल कानूनगो प्रबंधक बैंक ने बताया कि, खेती को उन्नत बनाने के लिए सरकार हर संभव कोषिष कर रही है कि आधुनिक तकनीक को खेती बाड़ी से जोड़ा जाकर सुविधा मुहैया कराई जाएं। एक ड्रोन की कीमत लगभग 13 लाख रुपए से 15 लाख के मध्य होती है। एक साधारण किसान इसका खर्च नहीं उठा पाएगा इसलिए सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है, कि ड्रोन फर्म एज-ए सर्विस प्लेटफार्म के माध्यम से किसानों को उपलब्ध हो इस के लिए नाबार्ड द्वारा संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराकर किसानों को सुविधा दी जा रही है। संस्था घुघरियाखेड़ी को नाबार्ड की ग्रामीण आधार भूत संरचना संवर्धन निधि (आरआईपीएफ) के अंतर्गत चयन करते हुए ड्रोन क्रय के लिए प्रोजेक्ट 13.10 लाख का तैयार किया गया था नाबार्ड से 9.94 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। संस्था के प्रोजेक्ट तैयार करवाने में अंबरीश वैद्य उप आयुक्त सहकारिता जिला खरगोन एवं बैंक के एमडी राजेन्द्र आचार्य तथा संस्था प्रशासक द्वारा सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया जाकर सहयोग प्रदान किया।

बैंक ने गतवर्ष की तुलना में विभिन्न क्षैत्रों में वृद्धि दर्ज की है- (राशि लाखों में)

नाम मद	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वृद्धि
अंशपूंजी	25303.31	25517.80	214.49
निधियां	34554.01	37646.06	3092.05
अमानतें	183060.67	206673.53	23612.86
शद्ध लाभ	1606.10	1647.30	41.20
संचित लाभ	3289.11	3390.05	100.94
कार्यशील पूंजी	392541.39	406990.04	14448.65
वर्ष की वसूली मांग	358563.79	379902.96	21339.17
वर्ष की मांग के विरुद्ध वसूली	276225.94	292596.16	16370.22
एनपीए का प्रतिशत			
एनपीए 5ः से अधिक नहीं होना चाहिए।	3.32	3.00	.0.32 कमी हुई
आडिट वर्गीकरण	ए	ए	

कृषक सदस्यों को 35.28. करोड़ रुपए का ऋण प्रदाय किया गया

कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाऐ जाने के उद्देश्य से केन्द्र/राज्य सरकार एवं नाबार्ड की पशुपालन कार्यशीलपूंजी ऋण योजना के तहत संस्थाओं के 7372 कृषक सदस्यों को 35.28. करोड़ रुपए का ऋण प्रदाय किया गया है। इससे कृषकों को कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, जिससे उनका आर्थिक विकास होगा। बैंक के कार्यक्षैत्र में आने वाले खरगोन एवं बड़वानी जिले के समस्त कृषक सदस्यों को सहकारिता की परिधि में लाया जाकर लाभाविन्त करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में संस्थाओं द्वारा 4376 कृषकों को नवीन सदस्यता प्रदान की गई है। इसके बाद अब कुल सदस्यों की संख्या 438435 हो गई है। इसमें से 267817 केसीसी खाताधारी ऋणी सदस्य है। बैंक की खरगोन एवं बड़वानी जिले में सभी शाखाएं कोर बैंकिंग अंतर्गत संचालित हो रही है। ग्राहकों एवं अमानतदारों को मोबाईल बैंकिंग अतर्गत समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जनसामान्य को लाभ पहुंचाने वाली सुविधाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना की सुविधा भी ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई है।

आय को बढ़ाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत

प्रदेश की अन्य बैंकों की तुलना में जिला सहकारी बैंक नवाचार के क्षेत्र में अग्रेणी बैंक के रूप में जानी जाती है, जिले की प्राथमिक संस्थाएं भी अपने कृषक सदस्यों की आवष्यकताओं की पूर्ति करें उन्हें समय पर ऋण प्रदाय हो तथा पर्याप्त मात्रा में कृषि आदान उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थाएं वर्तमान समय में ऋण/कृषि आदान उपलब्ध कराने तक सीमित न रहे संस्था की आय को बढ़ाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। संस्थाओं को पेट्रोल पम्प, एलपीजी का वितरण, तथा जेनरिक दवाइयों के लिए जन औषधि केन्द्र खोलने जैसे कार्य भी करना होंगे। इसके लिए केन्द्र/राज्य शासन स्तर से भी पर्यास हो रहे है। संस्थाएं इनका लाभ उठाएं और अपनी आय में वृद्धि करें। नाबार्ड संस्थागत विकास के लिए कार्य कर रही है उनकी योजनाओं का लाभ उठाते हुए नवीन तकनीक संस्था स्तर पर स्थापित करें। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के एमडी पीएस तिवारी, मनोज सिन्हा उप सचिव सहकारिता मंत्रालय भोपाल, विजेन्द्र पाटील डीडीएम नाबार्ड, बीएल मकवाना संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं बैंक प्रशासक अंबरीश वैद्य उप आयुक्त सहकारिता खरगोन गणेश यादव संभागीय शाखा प्रबंधक इंदौर मौजूद रहे।

ड्रोन किसानों के लिए उपयोगी,संस्था न्यूनतम किराए पर उपलब्ध कराएगी

धन्नालाल कुशवाह समिति प्रबंधक घुघरियाखेड़ी ने बताया कि- ड्रोन छिड़काव को एक प्रभावी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। स्प्रे पंप से छिड़काव के लिए एक दिन का समय लगता है। 250 रुपए से 300 प्रति एकड़ खर्च आता है जिससे लागत बढ़ जाती है। ड्रोन का उपयोग करके कीटनाशक के छिड़काव की लागत कम होती है और एक ड्रोन 10 मिनिट में एक एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। इस प्रकार कम समय में ज्यादा क्षेत्र में छिड़काव कर पाएंग। इस पद्धति से लागत में कमी समय एवं श्रम दोनों की बचत होगी वहीं पैदावार भी अच्छी होगी। मैनुअल छिड़काव से मशीन संचालनकर्ता श्रमिक के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव भी पड़ता था। ड्रोन स्प्रे करने का एक महत्वपूर्ण फायदा यह भी है कि ड्रोन की हवा से पूरा पौधा घूमता है इससे दवाई अच्छे से सक्रिय होने से पौधे पर दवाई का प्रभाव रहता है। स्प्रे पंप से किटनाशक दवाई का वेस्टेज भी होता है जबकि ड्रोन से किटनाशक दवाई का स्प्रे होने पर वेस्टेज नहीं होगा। इस प्रकार ड्रोन किसानों के लिए उपयोगी होकर संस्था द्वारा न्यूनतम किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा चूंकि अभी संस्था द्वारा प्रयोग के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। किसान के खेत की संस्था से दूरी, तथा ड्रोन संचालन में लगने वाले व्यय का आकंलन कर प्रति एकड व्यय नाबार्ड के नोडल अधिकारी की बैठक में निर्धारित कर लिया जाएगा। बैठक में वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। अमानत संग्रहण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मुख्य खरगोन, द्वितीय-पानसेमल एवं तृतीय बडवानी को प्रदान किया गया। कृषि ऋणों की वसूली के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार शाखा झिरन्या द्वितीय ऊन एवं तृतीय बैड़िया प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया गया। बैठक में बैंक संचालक मंडल के सदस्य एवं प्रतिनिधि कार्यक्रम का संचालन अनिल कानूनगो द्वारा किया गया। आभार संजय शर्मा क्षेत्रिय अधिकारी सेंधवा द्वारा माना गया।

अब अलग-अलग विभागों से डाटा लेकर एक जगह इकट्ठा किया जाएगा

वाटर मैनेजमेंट से प्रभावित यूनेस्को ने किया देश में सिर्फ ग्वालियर का चयन

ग्वालियर। जागत गांव हमार

ऐतिहासिक ग्वालियर शहर में राजशाही के समय बनाए बांधों और नहरों से किए वाटर मैनेजमेंट ने यूनेस्को को बहुत प्रभावित किया है। यहां के वीरपुर, रमौआ, मामा का बांध और तिघरा के माध्यम से शहर में होने वाली पानी की आपूर्ति ने ग्वालियर को देश का पहला ऐसा शहर बनाया है, जहां यूनेस्को द्वारा वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग विभागों से डाटा लेकर एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, जो भविष्य में बनने वाली पानी की आपूर्ति व उपयोग संबंधी योजनाओं में काम आ सकेगा। एक साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद देश के 150 अन्य शहरों में भी ये काम किया जाएगा। सिंधिया रियासतकाल के समय पर ग्वालियर के चार कोनों पर चार बांध तैयार किए गए थे। इनमें बारिश का पानी संग्रहित किया जाता था। इन बांधों की टापोलाजी कुछ इस प्रकार थी कि एक बांध का पानी दूसरे में और दूसरे का पानी तीसरे में आता था। इससे शहर का भूजल स्तर बना रहता था। वर्ष 1916 में शहर की 50 हजार की आबादी की पानी की जरूरत को पूरा करने तत्कालीन माधौ महाराज ने मैसूर रियासत के चीफ इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या से तिघरा बांध तैयार कराया था। यह भविष्य की तीन लाख आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।

16 लाख आबादी को मिल रहा पानी | यह आज 107 साल बाद भी 16 लाख की आबादी को पानी मुहैया करा रहा है। ग्वालियर नगर निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर शिशिर श्रीवास्तव ने यूनेस्को को ये पूरा डाटाबेस दिखाया था। इसमें कुओं-बावड़ियों की संख्या के साथ वाटर हार्वेस्टिंग सहित उपलब्ध पानी और प्रतिदिन उपयोग होने वाली पानी का डाटा मौजूद है। इस आधार पर गत मंगलवार को यूनेस्को नई दिल्ली की प्रतिनिधि नेहा ने ग्वालियर में कार्यशाला कर बताया कि ग्वालियर पहला ऐसा शहर है, जहां यूनेस्को वाटर मैनेजमेंट का काम करेगा।

ऐसे होगा वाटर मैनेजमेंट

ग्वालियर के वाटर मैनेजमेंट का एकजाई प्लान तैयार कर शहर के पानी के डाटा को एकजाई किया जाएगा। इससे निकट भविष्य में कभी भी पानी को लेकर कोई योजना बनेगी तो सारा डाटा एक ही स्थान पर आनलाइन मिल सकेगा। इसके लिए एक पोर्टल व डैशबोर्ड भी तैयार किया जाएगा। इसमें नगर निगम, जलसंसाधन विभाग, पीएचइ से डाटा एकत्रित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर देश के 150 अन्य शहरों में भी वाटर मैनेजमेंट की प्रकिया प्रारंभ की जाएगी।

बलराम तालाब योजना का किसान उठाएं लाभ

सिंचाई के लिए मिलेगा भरपूर पानी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने और बारिश के पानी का संरक्षण करने के लिए शिवराज सरकार द्वारा बलराम तालाब योजना चलाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। जिसके माध्यम से किसानों को सरकार तालाब बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जाता है। इन तालाबों का निर्माण किसानों के ही खेत पर किया जाता है।

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ

शासन की आधिकारिक वेबसाट के अनुसार बलराम तालाब योजना का मध्य प्रदेश के सामान्य, छोटे और सीमांत किसानों के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लाभ दिया जाता है।

योजना का उद्देश्य

बलराम तालाब योजना के माध्यम से भूमिगत और सतही जल की उपलब्धता को बढ़ाना है। ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जा सके। इन तालाबों के माध्यम से न सिर्फ खेत पर सिंचाई की जा सकती है, बल्कि इसके आस-पास मौजूद कुओं और नलकूपों के जलस्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलती है।

कैसे करें आवेदन

- क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन देना होगा
- आवेदन के आधार पर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी
- अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में भेजी जाएगी

मिलेगा अनुदान

- सामान्य वर्ग के कृषक को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार
- लघु सीमांत किसान को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रुपए
- अजाज के हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपए

सोयाबीन की उपलब्धता बीते वर्ष से 27 लाख टन ज्यादा

इंदौर। जागत गांव हमार

ताजा सीजन में सोयाबीन के उत्पादन के साथ उपलब्धता भी बढ़ गई है। क्रशिंग के लिए इस सीजन यानी तेल वर्ष 2022-2023 में बीते साल के मुकाबले 27 लाख टन सोयाबीन ज्यादा उपलब्ध है। दि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सोपा) ने यह रिपोर्ट जारी की है। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सोपा ने यह निष्कर्ष दिया है। सोपा द्वारा एक अगस्त तक की स्थिति का आंकलन कर बताया गया है कि इस सीजन में क्रशिंग के लिए कुल 141.76 लाख टन सोयाबीन उपलब्ध है। यह बिजाई के लिए सोयाबीन को निकालने के बाद शेष बची मात्रा है। बीते वर्ष से तुलना की जाए तो बीते वर्ष सिर्फ 113.27 लाख टन सोयाबीन ही क्रशिंग के लिए उपलब्ध था। सोयाबीन की खरीफ की बोवनी हो चुकी है।

तेजी की उम्मीद नहीं

दो माह बाद फसल बाजार में आ जाएगी। ऐसे में सोयाबीन की अच्छी उपलब्धता को देखते हुए बाजार में तेजी की उम्मीद नहीं है। सोयाबीन के साथ तेल के दामों में भी अब स्थिरता ही नजर आ रही है। सोयाबीन की अच्छी उपलब्धता का असर प्रतिद्वंद्वी खाद्य तेलों पर भी नजर आएगा।

ग्वालियर के किसान मेला की तैयारियों पर मंत्री ने की समीक्षा

भोपाल। जागत गांव हमार

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने सितम्बर के पहले सप्ताह में ग्वालियर में होने वाले किसान मेला की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ग्वालियर में एयरोपोनिक लेब और हाईटेक नर्सरी के भूमि-पूजन के निर्देश भी दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि

किसान मेला में उद्यानिकी कृषकों से संबंधित कृषि यंत्रों और कृषकों के लिये संचालित विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाये। उन्होंने कहा कि किसान मेला में जैविक खेती करने वाले कृषकों को सम्मानित भी किया जायेगा और ग्वालियर संभाग में माली प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिए जाएंगे।

संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र का लोकार्पण भी होगा। राज्य मंत्री कुशवाह ने उद्यानिकी फसलों की मंडी की स्थापना के संबंध में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, मंडी के अधिकारियों के साथ मण्डी से जुड़े व्यापारियों से सुझाव लेने के निर्देश दिए। उद्यानिकी मंत्री कुशवाह ने बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण जेएन कंसोटिया, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण निधि निवेदिता और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जागत गांव हमार पंचायत की विकास यात्रा, खलिहान तक के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते है कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)